योजनाओं के क्रियान्वयन का असर दिखना चाहिए

लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन का अर्थव्यवस्था पर असर दिखना चाहिए। उन्होंने औद्योगिक विकास योजनाओं में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए स्टेक होल्डर्स और विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने और गवर्नेंस में सुधार के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। वे बृहस्पतिवार को लोकभवन में सभी एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, नागरिक उड्डयन और एमएसएमई की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।

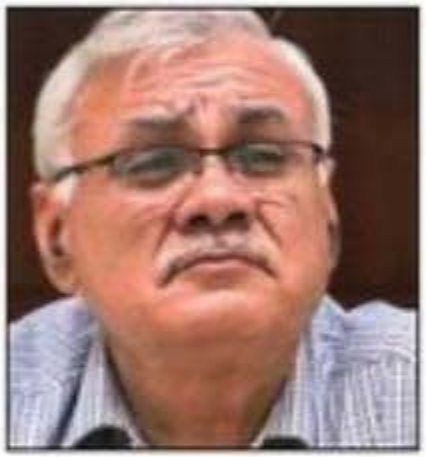

उन्होंने विभागीय कार्यों को आसान बनाने के लिए ई-फाइल का उपयोग बढ़ाने और सभी कार्यालयों में अच्छी कार्य संस्कृति विकसित करने के निर्देश दिए। कहा, इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और कार्यों के निस्तारण की गति में गुणात्मक सुधार आएगा। उन्होंने ओडीओपी की प्रशंसा की। नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने एयरपोर्ट निर्माण के मामलों में केंद्र सरकार से संवाद एवं संपर्क रखने के निर्देश दिए। उन्होंने यूपीडा की भी सभी योजनाओं को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूर्ण करने के निर्देश दिए। ब्यूरो

केंद्रीय योजनाओं से वेतन मद की राशि खर्च की अड़चन दूर

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय योजनाओं में शामिल वेतन मद की राशि खर्च होने में आ रही समस्या का समाधान कर दिया है। भुगतान के मॉड्यूल में विसंगति दूर होने तक वेतन मद की राशि कोषागार के जरिए जारी की जाएगी केंद्र सरकार के स्तर से संचालित कई योजनाओं का क्रियान्वयन पीएफएमएस के तहत एसएनए मॉड्यूल के माध्यम से होता है। लेकिन इस मॉड्यूल में वेतन से संबंधित कटौतियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इससे जिन केंद्रीय योजनाओं में वेतन से संबंधित मद शामिल हैं, उनमें कर्मचारियों के एनपीएस आदि की कटौती में समस्या आ रही है। अपर मुख्य सचिव वित्त एस राधा चौहान ने इस विसंगति को दूर करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ब्यूरो